RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : गुरुवार 02 नवंबर 2023 | वर्ष 05 | अंक 191 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

सीएम शिंदे की अध्यक्षता में

सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पारित

मुंबई: मराठा आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बुधवार (1 नवंबर) को संपन्न हुई, जिसमें सभी दल समुदाय को कोटा प्रदान करने पर सहमत हुए। सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा अपलोड किए गए एक पत्र में राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णयों का उल्लेख है।

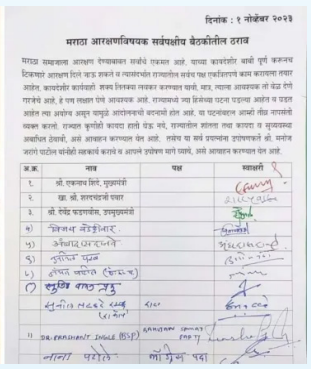

पत्र में उल्लेख किया गया है कि समुदाय की मांग के अनुसार कोटा प्रदान करने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। हालाँकि, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रक्रिया में समय लगेगा और कोटा की मांग करने वालों से सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय देने के लिए कहा गया है।

पत्र का अंत आंदोलन का चेहरा रहे मनोज जारांगे-पाटिल से अनशन खत्म करने और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील के साथ होता है। सीएमओ द्वारा एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर अपलोड किए गए पत्र में पारित प्रस्ताव पर नेताओं के नाम और उनके हस्ताक्षर भी हैं।

पत्र पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटिल, कांग्रेस नेता नाना पटोले, बालासाहेब थोरात और अन्य के हस्ताक्षर हैं।

पत्र में आंदोलन के नाम पर विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन की घटनाओं पर भी कड़ा संज्ञान लिया गया है।

सर्वदलीय बैठक के बयान में कहा गया है कि हिंसा की ऐसी घटनाएं मराठा आरक्षण विरोध को ''बदनाम'' करती हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं कि राज्य में किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

सेना (यूबीटी) ने राष्ट्रपति से मांगा समय

मराठा आरक्षण मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग की

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है और मराठा और धनगर समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

31 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा गया है कि सेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 5 या 6 नवंबर को राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। मराठा ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जबकि धनगर (चरवाहा) समुदाय एसटी (अनुसूचित जनजाति) का दर्जा चाहता है। मंगलवार को, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संसद के विशेष सत्र की मांग की और कहा कि इस मुद्दे को केंद्र द्वारा हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी केंद्रीय मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में आरक्षण का मुद्दा उठाना चाहिए। ठाकरे ने केंद्रीय मंत्रियों से (मराठा आरक्षण) मांग पूरी नहीं होने पर इस्तीफा देने का भी आग्रह किया।

पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं भड़क उठीं और मराठा आरक्षण समर्थकों ने कुछ राजनेताओं के आवासों और कार्यालयों में तोड़फोड़ की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जारांगे 25 अक्टूबर से जालना जिले के अपने अंतरवाली सरती गांव में अनशन पर हैं।

इस बार सर्दी में कम रहेगी सर्दी

नागपुर। अक्टूबर खत्म होने के बाद भी सर्दी ने अभी तक अपना असर नहीं दिखाया। नवंबर महीने में भी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। दोपहर में गर्मी का एहसास होता है, वहीं रात को गुलाबी ठंड महसूस होती है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान औसत से मामूली कम चल रहा है। मंगलवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ने जैसी स्थिति नहीं बन रही। कम दबाव का क्षेत्र तैयार नहीं हो रहा। अगले कुछ दिनों में चक्रवात या बारिश होने की संभावना नहीं है। इसीलिए तापमान सामान्य से केवल 1 या 2 डिग्री ही नीचे चल रहा है। वातावरण शुष्क बना हुआ है। अभी तक गर्म कपड़ों की मांग नहीं बढ़ सकी है।

कर्नाटक स्थापना दिवस से पहले क्यों लगा बैन

महाराष्ट्र के 3 मंत्री और 1 सांसद के लिए नो एंट्री

मुंबई: एमईएस संस्था द्वारा मनाए जा रहे ब्लैक डे में महाराष्ट्र के मंत्री और सांसद हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि प्रमुख व्यक्ति कोई ऐसा भाषण दे सकते हैं, जिससे भाषाई विवाद बढ़ जाएगा। उनके भाषणों से इससे कर्नाटक के मराठी निवासियों के उग्र होने की संभावना है। साथ ही इससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में, जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि जनता की शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, 31 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 2 नवंबर को शाम 6 बजे तक बेलगावी शहर और जिले की सीमाओं में इनके प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।

इस बीच एमईएस ने बुधवार को बेलगावी शहर समेत जिले के कई हिस्सों में ब्लैक डे मनाने की तैयारी की है। कन्नड़ समर्थक संगठन भी इसका विरोध कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने कानून-व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे संकट से निपटने और किसानों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई की

मुंबई : 13.4% वर्षा की कमी और रबी की बुआई में देरी के जवाब में, महाराष्ट्र ने 40 तालुकाओं में सूखे की घोषणा की है, जिससे केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए सहायता सीमा को दो से तीन हेक्टेयर तक बढ़ाकर समर्थन का विस्तार किया, जिससे किसानों की व्यापक श्रेणी को राहत प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

सूखे की घोषणाः महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण 40 तालुकाओं में सूखे की घोषणा की। यह निर्णय राहत और पुनर्वास विभाग की रिपोर्टों के आधार पर लिया गया था, जिसमें फसलों पर पानी की कमी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था।

केंद्र से तत्काल सहायताः सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति से निपटने

के लिए केंद्र सरकार से तत्काल सहायता मांगने की योजना की घोषणा की। राज्य मंत्रिमंडल ने सूखे की स्थिति के जवाब में इस कार्रवाई को अधिकृत किया है।

सूखा प्रबंधन संहिता पर विचारः सूखा घोषित करने का निर्णय 2016 के सूखा प्रबंधन संहिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिसमें नीति में उल्लिखित अनिवार्य और प्रभाव दोनों संकेतकों पर विचार किया गया।

राहत और पुनर्वास उपायः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने राहत और पुनर्वास विभाग को प्रभावित तालुकाओं के लिए उचित राहत पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश दिया। सरकार का इरादा प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई करने का है। वर्षा और कृषि प्रभावः महाराष्ट्र में वर्षा में 13.4% की कमी हुई, जिससे रबी की बुआई में देरी हुई। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण केवल 12 प्रतिशत बुआई ही पूरी हो पाई है। संशोधित सहायता सीमाएँ: सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता सीमा को दो हेक्टेयर से बढ़ाकर तीन हेक्टेयर कर दिया है। यह विस्तारित सहायता अब छोटी जोत वाले किसानों के अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अधिक किसानों को भी कवर करेगी।

प्रभावित किसानों के लिए सहायता में वृद्धिः इस निर्णय का उद्देश्य जून और अक्टूबर के बीच होने वाली अत्यधिक वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करना है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

दुर्घटनाओं को निमंत्रण

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी रपट में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों के जो आंकड़े सामने आए, वे निराश और चिंतित करने वाले हैं। इस रपट के अनुसार बीते वर्ष कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान गई और 4,43,366 लोग घायल हुए। उक्त रपट यह भी बताती है कि सड़क हादसों की संख्या में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनसे होने वाली मृत्यु की दर 9.4 प्रतिशत बढ़ी। इसी तरह सड़क हादसों में घायल होने वालों की संख्या में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसका अर्थ है कि मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के जो दावे किए जा रहे थे, वे खोखले निकले। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण तेज गति से वाहन चलाना है। हर कोई इससे अवगत है कि नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनने के साथ सड़क हादसे इसीलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर उनमें चलने वाले वाहन तय गति सीमा का उल्लंघन करते हैं। इस पर रोक लगाना सरकारों का दायित्व है, लेकिन वे इसमें विफल हैं। इस विफलता का बड़ा कारण संख्याबल की कमी से जूझती यातायात पुलिस है। एक समस्या यह भी है कि यातायात पुलिस कर्मी इसके प्रति सजग नहीं कि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन न करें।

एक्सप्रेसवे, हाईवे और राजमार्गों पर ओवर स्पीडिंग जानलेवा दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने का ही काम करती है, लेकिन न तो वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार हैं और न ही सरकारें एवं यातायात पुलिस। बीते वर्ष सड़क हादसों में 66 हजार से अधिक लोगों ने इसलिए जान गंवाई, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी या फिर हेलमेट नहीं लगाया था। स्पष्ट है कि वाहन चालक जानते-बूझते हुए जोखिम मोल लेते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई लोग राजमार्गों पर भी उलटी दिशा में वाहन चलाने लगते हैं। इसी तरह वे कहीं पर भी वाहन पार्क कर देते हैं।

यह सब रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन वे यह समझने को तैयार नहीं कि मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की बढ़ती संख्या देश को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम करती है, क्योंकि सड़क हादसों में मरने वाले अधिकांश लोग अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। बढ़ते सड़क हादसों पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का यह कहना एक सीमा तक ही उचित है कि हादसे रोकना केवल सरकार का काम नहीं, लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। निःसंदेह लोगों को सचेत होना होगा, लेकिन इसी के साथ सरकारों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वे इससे अनभिज्ञ नहीं कि औसत भारतीय यातायात नियमों समेत हर तरह के नियम-कानूनों के पालन के प्रति सजग नहीं। जब वे नियम-कानूनों का पालन कराने वाली एजेंसियों को अपना काम ढंग से करते नहीं देखते तो और अधिक लापरवाह हो जाते हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समाज का भिवंडी तहसीलदार कार्यालय पर धरना, मोर्चा

मुस्तकीम खान

भिवंडी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर श्रमजीव संगठना के नेतृत्व में भिवंडी तहसीलदार कार्यालय के सामने मोर्चा निकाल कर धरना दिया। तालुका के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आदिवासी पाड़ों तक संपर्क सड़क बनाने और आंतरिक सड़कें बनाने को तुरंत मंजूरी देने, जिन आदिवासी पाड़ों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां स्वच्छ और पीने योग्य पानी स्थायी रूप से उपलब्ध कराने, बिजली से वंचित गांवों में बिजली पहुँचाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर भिवंडी तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष व महिलाएं शामिल होकर अपनी मांग के लिए हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे।

गौरतलब है की भिवंडी शहर और ग्रामीण भागों में रह रहे आदिवासी समाज के लोगों को आज भी मौलिक सुविधा सरकार उपलब्ध नहीं कर पाई है जिसके कारण आज भी आदिवासी समाज कष्ट और परेशानी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं अपनी समस्याओं को लेकर इससे पहले भी

आदिवासी समाज के लोगों ने भिवंडी प्रांत वह तहसीलदार कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकालकर अपनी मांगों के लिए सरकार को निवेदन दिया मोर्चे में शामिल आदिवासी समाज के लोगों ने बताया की सरकार के सारे दावे कागजों पर हैं मुंबई जैसे अत्याधुनिक शहर से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में आज भी आदिवासी समाज अपने घरों की जमीन की मालिकी का हक, पीने का पानी और बिजली जैसी सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। भिवंडी तहसीलदार को सौंप गए ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्राम पंचायतें और महानगर पालिका क्षेत्रों में जिन परिवारों की संपत्तियों पर कर नहीं लगाया गया है। उन पर कर लगाया जाना चाहिए और उनके नाम की घरपट्टी जारी किया जाना चाहिए। तालुका में स्वीकृत वन दावेदारों में से 7/12 को पंजीकृत किया जाना चाहिए और 7/12 को वन दावेदारों को तुरंत वितरित किया जाना चाहिए। लंबित वन दावों की खोज की जानी चाहिए और तुरंत निपटारा किया जाए।

वंचित आदिवासी परिवारों को जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, घरकुल योजना दी जायें। ऐसे तमाम मांगो को लेकर ठाणे जिला कातकरी इकाई प्रमुख जयेंद्र गावित, तालुका प्रमुख आशा वाघे, भिवंडी शहर प्रमुख गुरुनाथ वाघे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार अधीक पाटिल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन में श्रमजीवी संगठना के पदाधिकारी दशरथ भालके, सुनील लोणे, सागर देसक, जया पारधी, अंकुश जाधव, अमोल मुकने,राजेश चन्ने, नारायण जोशी, दुष्यन्त घायवाट आदि पदाधिकारी सहभागी हुए थे।तहसीलदार कार्यालय के सामने दिन भर चले इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों आदिवासी महिला-पुरुष मौजूद थे।

इस वजह से डिप्टी CM अजित पवार ने पब्लिक कार्यक्रमों से बनाई दूरी, प्रफुल पटेल ने किया खुलासा

मुंबई : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को डेंगू हो गया है. एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उन जिन अटकलों और मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अजीत पवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन्हें कल से डेंगू का पता चला है और उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए चिकित्सा मार्गदर्शन और आराम की सलाह दी गई है. अजित पवार अपनी सार्वजनिक सेवा जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं. प्रफुल पटेल ने कहा कि एक बार जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो वह अपने समर्पित सार्वजनिक कर्तव्यों को जारी रखने के लिए पूरी ताकत से वापस आएंगे.

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल के ट्वीट के बाद अब तमाम मीडिया रिपोर्टस में जो कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है उसपर अब विराम लग गया है. प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी है कि अजित पवार को डेंगू हुआ है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी की सीटों को बढ़ाने की दिशा में काम करते हुए अजित पवार ने राज्य में अपना दौरा शुरू कर दिया था. अब डेंगू से ठीक होने के बाद ही वो आगे अपने दौरो को फिर से सुचारू रूप से करेंगे.

मुंबई में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. बृहन्मुंबई नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर महीने में डेंगू के 1360 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा नगर निकाय की मानसून की बीमारियों की लिस्ट में बताया गया कि मुंबई में जून महीने में डेंगू के 353 और जुलाई महीने में 413 मामले सामने आए थे. सितंबर महीने में डेंगू के मामले बढ़ते चले गए.

मुंबई के पास ओवरहेड उपकरण टूटने से रास्ते में खड़ी रहीं 12 ट्रेनें, गुजरात जाने वाले लोग परेशान

मुंबई : महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू रेलवे स्टेशन के पास ओवरहेड उपकरण खराब होने के कारण पश्चिमी रेलवे मार्ग पर गुजरात जाने वाली सभी ट्रेनें लगभग 12 घंटों तक रुकी रहीं। अप लाइन आधी रात करीब 12 बजकर 15 मिनट पर बहाल हुई, जबकि गुजरात की ओर जाने वाली डाउन लाइन बुधवार सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर बहाल हुई।

रेल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दहानू, मुंबई से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रेन यात्रा में आम तौर पर आठ घंटे का समय लगता है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि बीती रात 11 बजे दहानू रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड उपकरण खराब (ओएचई ब्रेकडाउन) हो गया था।

लोकल ट्रेन हुई रद्द, जानें क्या है वजह

उन्होंने बताया कि मुंबई की ओर जाने वाली अप लाइन आधी रात करीब 12 बजकर 15 मिनट पर बहाल हुई, जबकि गुजरात की ओर जाने वाली डाउन लाइन बुधवार सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर बहाल हुई।

अधिकारी ने बताया कि ट्रेनों की आवाजाही बहाल होने के बाद इस खंड पर ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है। पश्चिम रेलवे के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वनगांव और दहानू स्टेशनों के बीच हुई इस घटना के कारण मंगलवार देर रात मुंबई से रवाना होने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई।

पश्चिम रेलवे के मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, दहानू रोड और वनगांव स्टेशनों के बीच ओएचई टूटने के कारण गुजरात की ओर जाने वाली विभिन्न ट्रेनों में देरी हुई है । यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। असुविधा के लिए खेद है।''

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 02 नवंबर 2023

मध्यावधि चुनाव होना तय - जितेंद्र आव्हाड

मुंबई, राज्य में मध्यावधि चुनाव या राष्ट्रपति शासन लग सकता है, यह दावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रतोद विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए किया है। विधायक अयोग्यता मामले पर बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री अयोग्य घोषित होते हैं तो हम उन्हें उच्च सदन में ले आएंगे। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे गुट और दादा गुट के ८० विधायक संयुक्त रूप से अयोग्य घोषित किए जाएंगे, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव होना तय माना जा रहा है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों के ८० विधायक संयुक्त रूप से अयोग्य घोषित किए जाएंगे, इसका दुष्परिणाम फिर चुनाव में देखने को मिलेगा।

राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और वे अपने पद से इस्तीफा दें। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रतोद-विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी मीडिया से बात करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। जितेंद्र आव्हाड ने आगे कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में अस्थिरता का माहौल बन गया है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील ने पहले ही शिंदे सरकार को ४० दिन का समय दिया था। उस समय सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए फिर से आंदोलन करना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं होने पर मनोज जरांगे पाटील ने एक बार फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लिहाजा, मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य का माहौल एक बार फिर गरमा गया है। खासकर मराठवाड़ा के कई जिलों में यह आंदोलन हिंसक हो गया है। इस स्थिति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उन्हें नैतिकता दिखाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में दलबदल कर सरकार गिराने का काम चल रहा है।

मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक के लिए उद्धव शिवसेना को नहीं मिला आमंत्रण, राउत का फूटा गुस्सा

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अब इसी बैठक पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। राउत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में केवल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को बुलाया गया था। मराठा आरक्षण पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है, 'उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है और वह यह भी मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द फैसला होना चाहिए। आप गद्दार लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील और समावेशी राज्य माना जाता है। सीएम और डिप्टी सीएम ने मराठा लोगों से कई वादे किए थे। यह आंदोलन इसलिए है क्योंकि उन्होंने वादाखिलाफी की है।'

मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय प्रस्ताव भी जरांगे को नामंजूर

कहा- सरकार बताए, उसे कितना समय और क्यों चाहिए?

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की गुत्थी सुलझाने के लिए बुधवार (1 नवंबर) को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दलों के नेताओं ने मराठा समाज को आरक्षण देने पर सहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पास कर आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल से अनशन वापस लेने का आ''ान किया। जरांगे पाटिल पर इस प्रस्ताव का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। जरांगे ने साफ कह दिया है कि यदि पूरे मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र देकर आरक्षण देने की मांग पूरी न की गई तो वह गुरुवार से जल का भी त्याग कर देंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी संस्थापक शरद पवार सहित महाराष्ट्र के लगभग सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सभी के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मराठा समाज को आरक्षण देने पर सभी एकमत हैं।

'हिंसा से आंदोलन की बदनामी हो रही है'

कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय में टिकने योग्य आरक्षण देने पर सभी दल मिलकर काम करने को तैयार हैं। जल्द ही ये कार्यवाही पूरी की जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगेगा, वह मिले। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में हो रही हिंसा से आंदोलन की बदनामी हो रही है। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए।

आरक्षण मिलने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे- जरांगे

प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसमें मनोज जरांगे पाटिल भी सहयोग करें और अपना अनशन समाप्त करें। लेकिन यह सर्वदलीय प्रस्ताव सामने आने के कुछ ही देर बाद जालना के अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया कि आरक्षण मिलने तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

सरकार को कितना समय चाहिए और क्यों चाहिए?

उन्होंने कहा कि सभी मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाए, मैं अपनी इस मांग पर कायम हूं। सर्वदलीय प्रस्ताव में जरांगे से समय देने की मांग की गई है। इस पर बोलते हुए जरांगे ने कहा कि मेरे अनशन पर बैठने के 7-8 दिन बाद कह रहे हैं कि समय चाहिए। सरकार बताए, उसे कितना समय चाहिए और क्यों चाहिए। समय लेने के बाद क्या वह सभी मराठों को आरक्षण देने को तैयार है।

सरकार को और समय देना है या नहीं, बात करके तय करेंगे. हालांकि, जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि वह मराठा समाज से बात करके ही तय करेंगे कि सरकार को और समय देना है या नहीं। उन्होंने सोमवार को मराठा आंदोलनकारियों द्वारा की गई हिंसा के बाद आंदोलनकारियों पर हो रही पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया।

हिंसा की छुटपुट घटनाएं

मंत्री और अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ हिंसा की छुटपुट घटनाएं बुधवार को भी जारी रहीं। राज्य सरकार में मंत्री हसन मुश्रिफ की कार मराठा आंदोलनकारियों ने क्षति पहुंचाई है।

सरकार मुंबई में प्रदूषण की बीमारी को रोकने में असफल है तो इसे मेडिकल इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित कर देती है? विपक्ष हुआ आक्रामक

मुंबई, मुंबई में हवा की गुणवत्ता दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। मुंबई के लोगों को प्रदूषण के रूप में स्लो पॉइजन मिल रहा है। विपक्ष मुंबई में प्रदूषण की समस्या को लेकर रोज सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन मनपा प्रशासक हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और जो कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष ने राज्य की गद्दार सरकार पर जानबूझकर मुंबई की हवा खराब करने का आरोप लगाते हुए मुंबईकरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार बताया है। सरकार से मांग की है कि यदि सरकार मुंबई में प्रदूषण की बीमारी को रोकने में असफल है तो इसे मेडिकल इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित कर देती है? इस बारे में मनपा में पूर्व विपक्ष नेता रहे रवि राजा ने सरकार को पत्र लिखा है कि खराब प्रदूषण से मुंबईकरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उन्हें कई तरह की बीमारियां घेर रही हैं, ऐसे में सरकार को मुंबई में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए, ताकि वे खुद ही इनसे लड़ सकें। रवि राजा ने इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है।

३५,००० संविदा कर्मचारियों का स्थाई सेवा में समायोजन की

मुख्य मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू

मुंबई, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आनेवाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत लगभग ३५,००० संविदा कर्मचारियों ने स्थाई सेवा में समायोजन की मुख्य मांग को लेकर २५ अक्टूबर से विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इसी क्रम में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे सोमवार से मुंबई के आजाद मैदान में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, इसके बावजूद घाती सरकार इस हड़ताल की अनदेखी कर रही है।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में साल २००७ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में संविदा आधार पर पदों की भर्ती की गई है। कई कर्मचारी १०-१५ सालों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। संविदा के आधार पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का चयन परीक्षा, साक्षात्कार जैसी निर्धारित पद्धति के माध्यम से किया गया है। साल २००९ से संविदा कर्मचारी संवैधानिक माध्यमों से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, मणिपुर राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान, अवकाश अधिनियम, निश्चित सेवानिवृत्ति तक सेवा गारंटी जैसी सुविधाएं लागू की हैं। फिलहाल, राज्य भर में ४०,००० से ज्यादा पद खाली हैं। ऐसे में हड़ताल में शामिल प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि एनएचएम के तहत काम करनेवाले कर्मचारियों को इन रिक्तियों पर समायोजित किया जाए।

२५ अक्टूबर से राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के संविदाकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इन कर्मचारियों से बात करने को तैयार नहीं हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले दस महीने से हम अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास हमसे मिलने का समय ही नहीं है। ऐसे में हमें मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा है।

आयुष के तहत ६५० डॉक्टर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के तहत २,५०० डॉक्टर, टीबी रोग विभाग के २,५७३ कर्मचारी व तकनीशियन, २,००० प्रयोगशाला तकनीशियन, लगभग ४,००० पैरा-नर्स, ८,५०० सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग ३५ हजार संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं।

संविदा पर काम करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्यमंत्री तानाजी सावंत इस हड़ताल को लेकर गंभीर नहीं हैं। इसमें शामिल डॉक्टरों का कहना है कि 'सरकार आपके द्वार' वाला विज्ञापन बहुत ही भारी है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर यह फुसकी बम की तरह ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने घाती सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को इसी तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सत्ता में बैठे विधायकों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर भरोसा नहीं है क्या? -सुप्रिया सुले

मुंबई, मराठा आरक्षण मुद्दे पर कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने राज्यपाल भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। मनोज जरांगे पाटील अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य में जगह-जगह आक्रामक आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। आंदोलनकारी विधायकों की गाड़ियां रोकते, नेताओं का घेराव करते नजर आ रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में नागरिकों के गुस्से को देखते हुए कई विधायक अब मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सत्ताधारी दलों के कुछ विधायकों ने कल मंगलवार दोपहर राज्यपाल भवन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को लेकर राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने सत्ताधारी पार्टियों पर तंज कसा है। सांसद सुप्रिया सुले ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। मराठा आरक्षण मुद्दे पर कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने राज्यपाल भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल से भी मुलाकात की। इसका अर्थ क्या है? सत्ता में बैठे विधायकों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर भरोसा नहीं है क्या? खास बात यह है कि कल वैष्ठबिनेट की अहम बैठक थी। मराठा आरक्षण पर चर्चा होनेवाली थी। स'ाद्रि गेस्ट हाउस (जहां वैष्ठबिनेट की बैठक हुई थी) राजभवन से केवल पांच से छह मिनट की दूरी पर है, वहां विधायक विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी विधायक वहां नहीं गया।

सुप्रिया सुले ने कहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने स'ाद्रि गेस्ट हाउस छोड़कर गवर्नर हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि इन विधायकों को अब सरकार पर भरोसा नहीं है।

मुंबई को 250 नए आपला दवाखाने मिलेंगे

मुंबई : मुंबई को 250 नए आपला दवाखाने मिलने की तैयारी है। मंगलवार को मुंबई के संरक्षक मंत्री और कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की बीएमसी प्रशासक इकबाल सिंह चहल और नागरिक निकाय के सभी चार अतिरिक्त आयुक्तों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में छात्र अध्ययन स्थल, कौशल विकास केंद्र, क्रेच या बच्चे के बैठने की सुविधा, रोगी सहायता केंद्र, कब्रिस्तान से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक शौचालय, उद्यान, अपशिष्ट निपटान, मालाबार हिल जलाशय की क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

15 जनवरी से मुंबई में 25 नए रोगी सहायता केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। लोढ़ा को बताया गया कि कब्रिस्तानों के नवीनीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और काम जनवरी 2024 में शुरू होगा। दिवाली के बाद, अलग-अलग कचरा डिब्बे वितरित किए जाएंगे। सोसायटियों को सूखा और गीला कचरा अलग-अलग करना होगा।

बैठक में मालाबार हिल जलाशय के विस्तार पर भी चर्चा हुई और बैठक में काम रोकने का फैसला लिया गया. परियोजना की समीक्षा करने के लिए, आईआईटी मुंबई के निदेशकों, बीएमसी अधिकारियों और मालाबार हिल के निवासियों द्वारा सुझाए गए तीन आईआईटी प्रोफेसरों की एक समिति गठित की गई है। उक्त कमेटी एक माह के अंदर निर्णय लेगी.

बीएमसी का लक्ष्य 2 महीने में शिवाजी पार्क को धूल मुक्त बनाया

मुंबईः शिवाजी पार्क में धूल की समस्या को रोकने और मैदान को नया रूप देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने मंगलवार को टठर प्रमुख राज ठाकरे के घर पर बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक की।

शेवाले के अनुसार, 2021 में बीएमसी के शिवाजी पार्क सौंदर्यीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में जमीन पर मिट्टी बिछाई गई थी। सांसद ने आरोप लगाया कि मिट्टी बिना दिमाग लगाए बिछाई गई, इसलिए नागरिकों को धूल की समस्या का सामना करना पड़ा।

सांसद ने यह भी कहा कि पार्क में एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर्थ व्यायामशाला (जिम), स्काउट गाइड हॉल, बैठने की व्यवस्था का नवीनीकरण, जमीन को बनाए रखने और जमीन की रोशनी के लिए माहिम

सीवेज जल उपचार संयंत्र से पानी लाने जैसी संरचनाओं का नवीनीकरण भी किया जाएगा।

बीएमसी अगले दो महीनों में शिवाजी पार्क को धूल मुक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है। ढीली मिट्टी को हटाया जाएगा और धूल को नीचे गिराने के लिए मैदान में आठ स्मॉग गन भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जमीन पर हरी घास भी उगाई जाएगी। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक नियमित रूप से जमीन पर पानी का छिड़काव किया जाएगा.

शिवाजी पार्क में प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग आते हैं। खिलाड़ी, निवासी, कॉलेज के छात्र और पर्यटक अक्सर आते हैं। हर साल पार्क में कई रैलियाँ और राजनीतिक सभाएँ भी आयोजित की जाती हैं। 1.2 किमी के दायरे के साथ कुल क्षेत्रफल 28 एकड़ है। समुद्र के निकट होने के कारण हवा का वेग भी अधिक है। हवा के कारण मैदान और आसपास धूल फैल गई। आजकल मुंबई का अदकहाई है.

ठाणे में अज्ञात शव मिला

ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 'मुंब्रा क्रीक' में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। स्थानीय निकाय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि चूहा पुल से गुजर रहे कुछ लोगों ने मंगलवार शाम को क्रीक में शव देखा और स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

उन्होंने बताया कि स्थानीय दमकलकर्मी और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। मृतक की उम्र करीब 30 साल है।

अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है।

पुणे में पंद्रह हजार लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र दिया गया

पुणेः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिला कलेक्टरों को कुनबी प्रमाण पत्र वितरित करने के आदेश जारी किए हैं क्योंकि राज्य भर में मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिलाने का माहौल गर्म हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में, 1 जनवरी, 2022 से 31 अक्टूबर (मंगलवार) तक, अकेले पुणे जिले में लगभग 1,520,000 लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र दिए गए हैं, कलेक्टर डॉ. के अनुसार। राजेश देशमुख ने मंगलवार को कहा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र जारी करते समय 1967 से पहले के राजस्व प्रमाणों की जांच की गई है।

मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र दिलाने के लिए मनोज जारांगे-पाटिल ने अनशन शुरू किया है. इससे राज्य में माहौल गरमा गया है. उनकी भूख हड़ताल को पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है. गांव-गांव नागरिक उहोशना पर बैठे हैं. इस कारण कई जिलों से कुनबी प्रमाण पत्र देने की मांग बढ़ गयी है. उस पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला

कलेक्टरों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी जारी किए हैं। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इस संबंध में वीडियो सिस्टम के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों की बैठक भी ली. उन्होंने ऐसे आदेश भी दिये हैं.

अब तक तेरह हजार आवेदन

हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्य में कुनबी प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया है, लेकिन पुणे जिले में कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है. 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर तक लगभग 12 हजार 911 आवेदन प्राप्त हुए। राजस्व प्रमाणों की जांच के बाद अब तक उनमें से 12 हजार 294 को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। कुल आवेदनों की तुलना में प्रमाणपत्र आवंटन अनुपात 96 प्रतिशत है। कलेक्टर देशमुख ने बताया कि इनमें से 460 आवेदन लंबित हैं और संबंधित प्रांतीय अधिकारियों और तहसीलदारों को आदेश दिए गए हैं कि आवेदकों को वंशावली प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल आवेदनों में से 157 आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं. यह कुल आवेदनों की संख्या का मात्र एक प्रतिशत है.

शिंदे सरकार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा निशाना, बोले- 31 दिसंबर को हो जाएगी उनकी विदाई

मुंबई। ''उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसला करें, जिनमें दोनों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है''

उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की विदाई हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसला करें, जिनमें दोनों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है।

ठाकरे ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नार्वेकर को पढ़कर सुनाने के लिए भी कहा। पीटीआई के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''हम 31 दिसंबर को अयोग्य सरकार को अलविदा कहेंगे।'' बता दें कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी नहीं होने देनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से अजित पवार गुट के 9 विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के अनुरोध वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की याचिका पर भी 31 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा है।

मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्मः मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बुधवार को मुंबई में समाप्त हो गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों की राय मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ''सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए...यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें...यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है...आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com